Examrace: Downloaded from examrace.com

For solved question bank visit doorsteptutor.com and for free video lectures visit Examrace YouTube Channel

एनसीईआरटी कक्षा 9 राजनीति विज्ञान अध्याय 5: संस्थानों के कार्य यूट्यूब व्याख्यान हैंडआउट्स for Competitive Exams

Doorsteptutor material for UGC is prepared by world's top subject experts: Get detailed illustrated notes covering entire syllabus: point-by-point for high retention.

Get video tutorial on: Examrace Hindi Channel at YouTube

लोकतंत्र सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि संस्थाओं का काम है (कार्यों में भाग लेने के लिए की गई व्यवस्था)

3 संस्थाएं

- न्यायपालिका - सर्वोच्च न्यायालय एक ऐसी संस्था है जहां नागरिकों और सरकार के बीच विवाद समाप्त हो गया है।
- कार्यकारी - सिविल सेवक, एक साथ काम कर रहे हैं, मंत्रियों के फैसले को लागू करने के लिए कदम उठाने के लिए जिम्मेदार हैं।
- विधान - प्रधान मंत्री और कैबिनेट ऐसे संस्थान हैं जो सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लेते हैं।

सरकारी आदेश

- कार्यालय ज्ञापन
- प्राधिकारी और हस्ताक्षर जारी करना - अधिकारी केवल निर्देश लागू करते हैं
- एक दिन में सैकड़ों आदेश जारी किए जाते हैं
- 1 पृष्ठ से कई पृष्ठ हो सकते है
- उदाहरण के लिए, भारत सरकार के तहत नागरिक पदों और सेवाओं में 27 % की रिक्तियों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग (एसईबीसी) के लिए आरक्षित किया गया है - एसटी / एससी के बाद नई श्रेणी

पृष्ठभूमि

- 1979 में स्थापित दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बी पी मंडल की अध्यक्षता में था और वह मंडल आयोग के रूप में जाना जाता है।
- भारत में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए मानदंड निर्धारित करें
- आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट दी और आरक्षण के लिए सिफारिशें कीं
- जनता दल ने वादा किया है कि सत्ता में आने पर मंडल आयोग की रिपोर्ट आएगाऔर वी. पी. सिंह प्रधान मंत्री बने अंत में लागू किया गया और निर्णय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेजा गया।

- वहाँ विरोध थे और यह बहस किया गया था। इससे हजारों नौकरी प्रभावित हुई - कुछ के लिए यह उचित था लेकिन दूसरों के लिए यह अनुचित था। यहां तक कि अधिक योग्य लोगों को नौकरियों से वंचित किया गया था
- कुछ लोगों ने विवाद सुलझाने के लिए अदालत में मामला दायर किया
- 'इंदिरा साहनी और दूसरों के विरुद्ध भारत संघ मामले' । सुप्रीम कोर्ट के ग्यारह न्यायाधीशों ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुना। बहुमत से, 1992 में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने घोषणा की कि भारत सरकार का यह आदेश वैध था।
- अनुसूचित जाति ने सरकार के आदेश को संशोधित करने के लिए कहा और आरक्षण के लाभ प्राप्त करने से लोगों को अच्छी तरह से बाहर रखा जाना चाहिए

राजनीतिक संस्थानों की आवश्यकता

सरकार

- सुरक्षा सुनिश्चित करती हे
- शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करती हे
- करों को एकत्र और कार्यक्रमों पर पैसा खर्च करती हे
- कल्याणकारी योजनाएं तैयार और कार्यान्वित करती हे
- संस्थानों का कार्य करना
- नियमों और विनियमों को शामिल करते हैं
- बैठकों और दिनचर्या शामिल
- चूंकि वे लोगों के व्यापक सेट के लिए परामर्श लेने का अवसर प्रदान करते हैं विलंब और जटिलताए उपयोगी होते हैं

संसद

निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय विधानसभा - अंतिम कानून बनाने का प्राधिकरण (कानून बदल सकते हैं, नए कानून बना सकते हैं और मौजूदा कानूनों को खत्म कर सकते हैं)

राज्य स्तर पर इसे विधानसभा या विधायी विधानसभा के रूप में जाना जाता है

संसद सरकार पर नियंत्रण करती है

संसद में राष्ट्रपति और दो सदन, लोकसभा और राज्य सभा शामिल हैं। प्रधान मंत्री के पास बहुसंख्यक लोकसभा सदस्यों का समर्थन होना चाहिए।

इसका सार्वजनिक धन पर नियंत्रण है और जहां यह खर्च किया जाना चाहिए

विभिन्न मुद्दों पर चर्चा और बहस के लिए उच्चतम मंच

सदन / मंडलों का संसद

- लोक सभा (लोक सभा या लोअर चैंबर) - सीधे लोगों द्वारा निर्वाचित और वास्तविक शक्तियां हैं

- राज्य सभा (राज्य परिषद या ऊपरी कक्ष) - परोक्ष रूप से निर्वाचित और विशेष कार्य करता है

राष्ट्रपति संसद का हिस्सा हैं, लेकिन किसी भी घर के सदस्य नहीं हैं

राज्य सभा को ऊपरी सदन के रूप में जाना जाता है लेकिन वास्तव में लोकसभा जो सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करती है

- कोई भी साधारण कानून को दोनों घरों से गुजरना होगा, यदि अंतर है तो संयुक्त सत्र आयोजित किया जाता है और चूंकि लोकसभा के पास अधिक सदस्य हैं जो इसका प्रचलन करती है
- पैसे के मामलों में लोकसभा के पास अधिक शक्तियां हैं। राज्यसभा अस्वीकार नहीं कर सकती, लेकिन केवल 14 दिनों तक देरी कर सकती है
- लोक सभा मंत्रियों की परिषद नियंत्रित करती है। बहुमत के सदस्यों के साथ प्रधान मंत्री नियुक्त किया जाता है। यदि बहुसंख्यक लोकसभा सदस्यों के मंत्रिपरिषद में कोई आश्वासन नहीं होता है, तो प्रधान मंत्री सहित सभी मंत्रियों को छोड़ दिया जाएगा राज्यसभा में यह शक्ति नहीं है।

राजनीतिक कार्यकारी

आदेश पर हस्ताक्षर केवल कार्यकारी की जिम्मेदारी है

अधिकारी कार्यकारी सरकार के अधिकारी हैं जो रोजाना निर्णय लेते हैं लेकिन लोगों की ओर से सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं

वे सरकारी नीतियों के निष्पादन के प्रभारी हैं

- राजनीतिक कार्यकारी - लोगों द्वारा निर्वाचित राजनीतिक नेताओं और स्थायी कार्यकारी के लिए सर्वोच्च है वे निर्णय के परिणाम के लिए लोगों के लिए जवाबदेह हैं वे समग्र रूपरेखा और उद्देश्य तय करते हैं
- स्थायी कार्यकारी या सिविल सेवकों - जब सत्ताधारी पार्टी बदलती है तब भी कार्यालय में रहते हे । वे राजनीतिक अधिकारियों के अधीन काम करते हैं। वे अधिक शिक्षित हैं और इस विषय का विशेषज्ञ ज्ञान है।

प्रधान मंत्री और मंत्रिपरिषद

- प्रधान मंत्री
- राष्ट्रपति पीएम (बहुसांख्य पार्टी या गठबंधन पार्टी के नेता जो लोकसभा में बहुमत का आदेश देता है) नियुक्त करता है
- कभी-कभी, जो व्यक्ति संसद सदस्य नहीं है, वह भी मंत्री बन सकता है लेकिन ऐसे व्यक्ति को मंत्री के रूप में नियुक्ति के छह महीने के भीतर संसद के किसी एक सदन के लिए निर्वाचित करना होगा।
- प्रधान मंत्री सरकार का मुखिया हैं और वास्तव में सभी सरकारी शक्तियों का प्रयोग करते हैं वह मंत्रिमंडल बैठक में अधिकांश निर्णय लेते हैं।
- मंत्रिपरिषद आधिकारिक नाम है जिसमें सभी मंत्रियों को शामिल किया गया है
- कैबिनेट मंत्री आमतौर पर सत्ताधारी पार्टी या पार्टियों के शीर्ष स्तर के नेता हैं जो प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी हैं। इसमें करीब 20 मंत्रियों का समावेश है।

- स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री आम तौर पर छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं वे विशेष रूप से आमंत्रित होने पर ही मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेते हैं।
- राज्य के मंत्रियों को कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए जुड़ा हुआ है और उन्हें जरूरी है
- निर्णय के लिए सभी सदस्य नहीं मिल सकते हैं, इसलिए निर्णय कैबिनेट में होता है और इसलिए हमारे पास कैबिनेट के फार्म का सरकार है कैबिनेट एक टीम के रूप में काम करती है
- प्रत्येक मंत्रालय में सचिव होते हैं, जो सिविल सेवक हैं।
- सचिवों ने निर्णय लेने के लिए मंत्रियों को आवश्यक पृष्ठभूमि जानकारी प्रदान की।
- एक टीम के रूप में कैबिनेट की सहायता कैबिनेट सचिवालय द्वारा की जाती है इसमें कई वरिष्ठ सिविल सेवकों को शामिल किया गया है जो विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज का समन्वय करने का प्रयास करते हैं।

प्रधान मंत्री के अधिकार

- अध्यक्षों की कैबिनेट बैठकों
- विभिन्न विभागों के समन्वय
- विभिन्न मंत्रालयों पर पर्यवेक्षण
- मंत्रियों को काम का वितरण और पुनर्वितरण
- एक मंत्री को खारिज करने की शक्ति है
- शक्तियों की अधिकतर एकाग्रता - जे. एल. नेहरू, इंदिरा गांधी
- गठबंधन सरकार से प्रधान मंत्री निर्णय लेने के लिए उन्हें पसंद कर सकते हैं और अलग-अलग समूहों को समायोजित कर सकते हैं

राष्ट्र-पति

- देश में सबसे अधिक औपचारिक प्राधिकरण।
- नाममात्र शक्तियों के साथ राज्य के प्रमुख
- ब्रिटेन में रानी के समान और कार्य अधिक औपचारिक हैं
- राजनीतिक संस्थानों के कामकाज की निगरानी
- निर्वाचित सांसदों और विधायकों द्वारा आयोजित चुनाव और इसलिए नाममात्र कार्यकारी है
- संदर्भ -
- भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राज्यों के उच्च न्यायालयों की प्रमुख नियुक्तियां हैं,
- राज्यों के गवर्नर्स, चुनाव आयुक्त और अन्य देशों के राजदूत
- भारत के रक्षा बलों के सुप्रीम कमांडर
- वह मंत्रियों की परिषद की सलाह पर शक्तियां बजाते हैं

- संसद द्वारा पारित विधेयक कानून बनने के बाद ही कानून बन जाता है - राष्ट्रपति इसे देरी कर सकते हैं और इसे पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं
- राष्ट्रपति ने प्रधान मंत्री की नियुक्ति की, यदि कोई पार्टी स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो वह अपने विवेक का उपयोग करता है और नेता को नियुक्त करता है जो कि उनकी राय में लोकसभा में बहुमत का समर्थन मिल सकता है
- संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति सीधे निर्वाचित भारत निर्वाचित हैं और वे सभी मंत्रियों को चुनते हैं और नियुक्त करते हैं - *सरकार के राष्ट्रपति पद* 4 साल की अवधि के साथ । आमतौर पर लैटिन अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ के देशों में

न्यायतंत्र

- विभिन्न स्तरों पर न्यायालयों को न्यायपालिका के रूप में रखा गया है
- पूरे देश के लिए सुप्रीम कोर्ट, स्थानीय स्तर पर राज्यों, जिला न्यायालयों और अदालतों में उच्च न्यायालय। भारत में एक एकीकृत न्यायपालिका है
- यह कोई भी विवाद ले सकता है
  - देश के नागरिकों के बीच
  - नागरिकों और सरकार के बीच
  - दो या दो से अधिक राज्य सरकारों के बीच
  - संघ और राज्य स्तर पर सरकारों के बीच
- यह सिविल और आपराधिक मामलों में अपील की सर्वोच्च अदालत है
- यह उच्च न्यायालयों के फैसले के खिलाफ अपील सुन सकता है
- यह मौलिक अधिकारों के अभिभावक के रूप में कार्य करता है
- न्यायाधीश सत्ता में सरकार या पार्टी की दिशा में कार्य नहीं करते हैं
- प्रधान न्यायाधीश और भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श के साथ राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाता है
- इसका अर्थ है कि वरिष्ठ न्यायाधीश अब नए न्यायाधीश चुनते हैं
- संसद के दो सदनों के दो-तिहाई सदस्यों द्वारा अलग-अलग पारित एक महाभियोग गति द्वारा एक न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। यह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ है
- न्यायालयों में देश के संविधान की व्याख्या करने की शक्ति है। यदि वे संविधान के खिलाफ हैं तो वे विधायिका के किसी भी कानून या कार्यकारी कार्य के बारे में अवैध घोषित कर सकते हैं
- न्यायिक समीक्षा - वे किसी भी कानून या कार्यकारी की कार्रवाई की वैधता निर्धारित कर सकते हैं
- अनुसूचित जाति ने फैसला सुनाया है कि संविधान के मूल और बुनियादी सिद्धांतों को संसद द्वारा नहीं बदला जा सकता है

- अगर लोग सार्वजनिक हित सरकार के कार्यों से आहत होते हैं तो लोग न्यायालय में जा सकते हैं - सार्वजनिक हित याचिका
- न्यायालयों ने निर्णय लेने के लिए सरकार की शक्ति का दुरुपयोग रोकने और सार्वजनिक अधिकारियों के हिस्से पर भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए हस्तक्षेप किया। इसलिए, न्यायपालिका लोगों के बीच एक उच्च स्तर का आत्मविश्वास हासिल करती है।

-Mayank

Developed by: Mindsprite Solutions